



- उप राज्यपाल एडमिरल डी के जोशी ने कल द्वीप समूह में स्कूबा डाइविंग के प्रस्तावित गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के संबंध में राज निवास में तीसरी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
- नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने कहा कि हवाई यात्रा को सुलभ और सस्ता बनाना सरकार की प्राथमिकता है।
- केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि पुलिस स्टेशनों और पुलिस विभाग के नियंत्रण वाले स्थानों को गवाहों से पूछताछ के लिए निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए।
- विद्युत विभाग द्वारा कार निकोबार, कैम्पबेल बे और कर्पोटा के उपभोक्ताओं के लिए ऑनलाइन बिल भुगतान सेवा को सफलतापूर्वक चालू किया गया है।
- अण्डमान निकोबार प्रशासन ने न्यूनतम मजदूरी भाड़े में संशोधन किया है।



अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उप राज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी के जोशी कल द्वीप समूह में स्कूबा डाइविंग के प्रस्तावित गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के संबंध में राज निवास में तीसरी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अभ्यास का उद्देश्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह को वैश्विक डाइविंग गंतव्य सूची में डालना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। बैठक में अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र, पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव और अंडमान निकोबार कमांड के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में हिंद महासागर क्षेत्र में द्वीपों को एक प्रीमियम डाइविंग और पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए स्कूबा डाइविंग विश्व रिकॉर्ड बनाने के तौर-तरीकों पर चर्चा की गई।



नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने कहा कि हवाई यात्रा को सुलभ और सस्ता बनाना सरकार की प्राथमिकता है। श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई यात्रियों को दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान कराने के लिए प्रयासरत है।

नई दिल्ली में दूसरे एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में श्री नायडू ने देश में नागरिक उड्डयन के मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों को रेखांकित किया। उन्होंने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाने और विमानन क्षेत्र के लिए हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश पर जोर दिया।



केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि पुलिस स्टेशनों और पुलिस विभाग के नियंत्रण वाले स्थानों को गवाहों से पूछताछ के लिए निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दो हजार तेईस के अंतर्गत सभी पुलिस स्टेशनों को ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाहों से पूछताछ के लिए एक निर्दिष्ट स्थान की पहचान करने के लिए कहा गया है।



लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद भी शराब की बिक्री करने के आरोप में अबरडीन पुलिस थाना की टीम ने एक स्थानीय बार और रेस्तरां में छापा मार कर चार लाख रुपये से अधिक की भारत में बनी विदेशी शराब की बोतलें ज़ब्त की। सूचना के आधार पर अबरडीन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विशाल राम के नेतृत्व में इंस्पेक्टर मिथुन किरतोनिया और अन्य पुलिस कर्मियों ने गांधी मार्केट में स्थित होटल ए आर हनी हब में छापा मारा और बड़ी मात्रा में शराब की बोतलें ज़ब्त की।



भारत के जी-20 शेरपा, अमिताभ कांत ने कहा है कि देश ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर – डीपीआई की मदद से नौ वर्षों में जो उपलब्धि हासिल की है उसे डी पी आई के बिना हासिल करने में पचास वर्ष लग जाते। श्री अमिताभ कांत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत के जी-20 कार्य बल की अंतिम रिपोर्ट जारी करने के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत डिजिटलीकरण के मामले में बहुत आगे है और रेहड़ी-पटरी वालों से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक एकीकृत भुगतान प्रणाली-यूपीआई का इस्तेमाल होने से देश में वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा डिजिटल लेन-देन होता है। ।



विद्युत विभाग द्वारा कार निकोबार, कैम्पबेल बे और कमोर्टा के उपभोक्ताओं के लिए ऑनलाइन बिल भुगतान सेवा को सफलतापूर्वक चियान्वित किया गया है। इसका उद्देश्य इन क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बिना परेशानी और साईट कार्यालयों में आकर बिजली बिल का भुगतान करने से निजात दिलाना था। क्षेत्र के उपभोक्ता अब पहली जुलाई से ऊर्जा पे पोर्टल के माध्यम से अपने बिजली के बिलों का भुगतान कर सकते हैं। उपभोक्ताओं से इस नई सेवा का लाभ उठाने का अनुरोध किया गया है।



पशुओं में होने वाले पैर और मुंह की बीमारी की रोकथाम के लिए पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग द्वारा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष दो हजार पांच से शुरू किए गए इस अभियान के तहत इस वर्ष जून में भी दक्षिण अंडमान जिले में अभियान का उनतीसवां चक्र चलाया गया। वरिष्ठ पशु चिकित्सकों के नेतृत्व में दस टीकाकरण टीम बनाया गया और आठ हजार से अधिक पशुओं के अलावा डेढ़ हजार से अधिक भैंसों तथा गायों में नया टैग लगाया गया। पशुओं में विशेषकर गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि जानवरों में संक्रमण को रोकने के लिए इस तरह का अभियान चलाया जाता है। पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हर वर्ष छः महीने में एक बार टीकाकरण अभियान चलाकर देश में बीमारी को नियंत्रित करने के लिए यह अभियान चलाया जाता है।



अण्डमान निकोबार प्रशासन ने न्यूनतम मजदूरी भाड़े में संशोधन किया है। अब अकुशल मजदूरों को प्रतिदिन छह सौ तैंतीस रूपए प्रतिदिन की दर से मजदूरी मिलेगी। अर्धकुशल और अकुशल सुपरवाइजरी के लिए यह दर सात सौ चौदह रूपए होगी। कुशल और लिपिक श्रेणी के लिए आठ सौ सैंतीस रूपए प्रतिदिन, जबकि उच्च कुशल श्रेणी के लिए नौ सौ बीस रूपए प्रतिदिन की दर से मजदूरी भाड़ा निर्धारित किया गया है। आदेश की प्रतिलिपि श्रम विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। सभी संस्थानों के मालिकों से न्यूनतम मजदूरी भाड़े की दरों को सुनिश्चित करने और संशोधित दरों के हिसाब से कामगारों को भुगतान करने को कहा गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।



जवाहर लाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में स्नातक स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की श्रेणीवार अंतिम योग्यता सूची उन्नीस जुलाई को अपलोड कर दी जाएगी। परामर्श बाईस जुलाई से आरंभ होगा। इसके लिए विभिन्न विषयों के हिसाब से सारणी जारी की गई है। संबंधित उम्मीदवारों को परामर्श के लिए घोषित तारीखों में सुबह साढ़े आठ बजे मूल दस्तावेजों और इसकी प्रतिलिपि के साथ कॉलेज में उपस्थित रहने को कहा गया है।

उधर, अंडमान कॉलेज में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की अस्थायी सूची सामान्य कॉलेज प्रवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। दावे और आपत्तियां बाईस जुलाई की शाम पांच बजे तक मेल या कॉलेज के प्राचार्य के पते पर जमा किया जा सकता है।



डाइट गाराचरामा में दो वर्षीय डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की अंतिम योग्यता सूची सामान्य कॉलेज प्रवेश पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है। ह्यूमैनिटिस के लिए परामर्श बाईस जुलाई को सुबह नौ बजे से और विज्ञान के लिए योग्य उम्मीदवारों का परामर्श तेईस जुलाई को सुबह नौ बजे से डाइट गाराचरामा में लिया जाएगा। परामर्श के दिन चुने जाने वाले उम्मीदवारों को उसी समय प्रवेश दे दिया जाएगा। शुल्क की अदायगी भी करनी होगी। उम्मीदवारों को अपने मूल दस्तावेजों के साथ अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्रवेश के दिन जमा करने होंगे। परामर्श सत्र में भाग न ले सकने वाले उम्मीदवारों को और अवसर नहीं दिया जाएगा तथा योग्यता सूची में शामिल अगले पात्र उम्मीदवार को मौका मिलेगा।

